आकाशवाणी शिमला
18.11.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945 बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–नई करूणामूलक रोजगार नीति बनाएगी प्रदेश सरकार।
- आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना ने 3 सप्ताह में दस लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित कर हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा–पूरे देश ने नकारी कांग्रेस की झूठी गारंटियों की राजनीति।
- कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा–प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अधिक गुणवत्ता पर दे रही है जोर।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार नई करूणामूलक रोजगार नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खो देने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदकों का विभागवार ब्यौरा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार अधिक से अधिक आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं और अनाथों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता देकर आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

आयुष्मान वय वंदना

हाल में शुरू किए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह कार्ड वृद्ध नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर को लॉन्च किए जाने के तीन सप्ताह के भीतर हासिल की गई है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के तहत अब तक नौ करोड रूपये खर्च किये गए हैं। इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के चार हजार आठ सौ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ हुआ है, जिनमें एक हजार 4 सौ से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। इस कार्ड के तहत कई गंभीर बीमारियों में इलाज की सुविधा मिलती है। इस वर्ष सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम–जेएवाई के एक महत्वपूर्ण विस्तार को मंजूरी दी थी, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है।

आरक्षण

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में समाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है। इसका उद्देश्य शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना है। प्रवक्ता ने कहा कि वंचित वर्गों और विशेष समूह के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र होंगे और स्कूल किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इंकार नहीं कर सकते हैं।

मनसुख मांडाविया

राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेताओं के संवाद के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। मांडविया ने कहा कि यह मंच देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बातचीत करने और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। मांडविया ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य देश भर के युवाओं में प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है, साथ ही उन्हें विकसित भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करना है।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हटाए गए मुख्य संसदीय सचिवों को विधायक पद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने जो पैसा इन मुख्य संसदीय सचिवों पर खर्च किया है वह सारा पैसा वसूल कर वापस प्रदेश के खजाने में जमा किया जाना चाहिए।

हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिए जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब भी नगर निगम स्थापित हो तो विकास के कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए और सभी को मिलकर हमीरपुर के चौमुखी विकास पर काम करना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर को नगर निगम का दर्जा देने और यहां भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का कार्यालय खोलने के प्रदेश मंत्रीमंडल के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूरे देश ने कांग्रेस की झूठी गारंटियों को राजनीति को नकार दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के बाद शिमला लौटे जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय पूरे देश में हिमाचल की सुक्खू सरकार की नाकामियों के चर्चे हो रहे हैं। इससे हिमाचल की छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल शांत और प्रगतिशील राज्य के रूप में जाना जाता है लेकिन सुक्खू सरकार के दो साल के कार्यकाल ने हिमाचल की छवि को धूमिल कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से हिमाचल विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है जिसकी भरपाई करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपने हर चुनावी संकल्प को निर्धारित समय में पूरा करती है और इस नीति ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दिखाई है।

चंद्र कुमार

कृषि मंत्री व पशु पालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में विस्तार से अधिक गुणवत्ता पर जोर दे रही है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत चलवाड़ गांव में एक निजी स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूलों के साथ–साथ निजी स्कूलों ने भी शिक्षा के विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा

के विस्तार के लिए सभी सरकारों ने काम किया है लेकिन अब शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की है ताकि बच्चे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। उन्होंने इस मौके पर स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि शी हाट की तर्ज पर सोलन में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद विक्रय के लिए व्यवस्थित केंद्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। शांडिल आज सोलन में जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपनी और प्रदेश की आर्थिकी में सकारात्मक योगदान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बाद में जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के समाजिक–आर्थिक स्तर में सुधार के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का पात्र लोग तभी पूरा लाभ ले सकते है जब उन्हें इनकी पूर्ण जानकारी होगी।

डी.सी चंबा

चंबा जिला में प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की खरीद प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आज से आरंभ हो गई। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने चंबा के बालू से इस खरीद का विधिवत शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार 30 रूपए प्रति किलो की दर से ये खरीद कर रही है।

विंटर कार्निवाल

शिमला विंटर कार्निवाल इस बार 24 दिसम्बर से 2 जनवरी तक आयोजित होगा। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि विंटर कार्निवाल के लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। इस बार विंटर कार्निवाल दस दिन का होगा और इस दौरान शिमला घूमने आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को राज्य की विविध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।

महापौर ने कहा कि विंटर कार्निवाल को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक का एक दौर पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस बार कार्निवाल के उपलक्ष्य में एक सोविनियर भी प्रकाशित किया जाएगा जिसमें शिमला शहर के इतिहास की जानकारी उपलब्ध होगी।

रामकृष्ण मिशन

रामकृष्ण मिशन शिमला के सचिव तन्महिमानंद ने शिमला के पुलिस अधीक्षक पर रामकृष्ण मिशन मंदिर में हुई हिंसक घटना को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। तन्महिमानंद ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमालय ब्रहम समाज का कोलकता में शुरू हुए ब्रहम समाज से कोई नाता नहीं है और हिमाचल का ब्रहम समाज स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला रामकृष्ण मिशन मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश का है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, वे भू–माफिया से जुड़े हुए हैं। तन्महिमानंद ने ये भी कहा कि इस हिंसक घटना के बावजूद प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ काई कार्रवाई नहीं की।

मस्ज़िद मामला

राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने के नगर निगम की अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के मामले पर आज शिमला की जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के वकील ने पूरे मामले को फिर से नगर निगम आयुक्त के पास सुनवाई के लिए भेजने की मांग की ताकि इस मामले को फिर से ध्यान से सुना जा सके। मुस्लिम पक्ष के अभिवक्ता विश्व भूषण ने कहा कि जिला अदालत ने इस मामले में वक्फ बोर्ड से हल्फनामा मांगा है। हल्फनामे में ये स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ को अपना अधिकृत प्रतिनिधि घोषित किया था या नहीं। मामले पर अगली सुनवाई 22 नवम्बर को होगी।